DAILY NEWS BULLETIN

LEADING HEALTH, POPULATION AND FAMILY WELFARE STORIES OF THE Day Friday **20260102**

THE ECONOMIC TIMES

NPS के साथ हेल्थ इंश्योरेंस शुरू

Ramesh.Tiwari
@timesofindia.com

■ **नई दिल्ली:** अब NPS (नैशनल पेंशन सिस्टम) के तहत हेल्थ इंश्योरेंस का भी इंतजाम होगा। 'एनपीएस स्वास्थ्य' नाम की नई स्कीम में पेंशन खाते के साथ टॉप अप बीमा भी मिलेगा। इन दिनों हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ती शिकायतों के बीच यह अहम बात है कि पेंशन रेगुलेटर खुद पूरी स्कीम की निगरानी करेगा।



PFRDA प्रमुख एस. रमन

गुरुवार को एनपीएस दिवस पर एनपीएस स्वास्थ्य स्कीम की शुरुआत का ऐलान किया गया। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के प्रमुख एस. रमन ने बताया अक्सर बीमा होने पर भी इलाज का 30 से 40 फीसदी खर्च मरीज की अपनी जेब से होता है। हमारे प्रॉडक्ट एनपीएस स्वास्थ्य में हेल्थ के लिए एक पेंशन अकाउंट होगा। अस्पताल का शुरुआती खर्च इसी पेंशन खाते से दिया जाएगा, बाकी टॉप अप बीमा के जरिये के जरिये इलाज पर बड़ी रकम का खर्च उठाया जा सकता है।



AI Image

एक्सिस पेंशन फंड ने गुरुवार को ही एनपीएस स्वास्थ्य की शुरुआत करने का ऐलान किया। उसकी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, स्कीम में अधिकतम 30 लाख का कवर मिलेगा, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा, जब पहले तीन लाख रुपये का खर्च मरीज के खाते से हो जाए। इस खाते को पेंशन फंड चलाएंगे, जिसका पैसा इक्विटी में कम, डेट जैसे कम उथल-पुथल वाले प्रॉडक्ट में ज्यादा लगाया जाएगा।

एस. रमन ने बताया कि ग्रुप पॉलिसी होने के नाते टॉप अप बीमा का प्रीमियम काफी कम होगा। यह प्रॉडक्ट मार्केट से जुड़े लोगों के सुझाव पर ही लाया गया। हम उम्मीद करते हैं। बहुत सी कई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां इसके लिए पेंशन फंड्स के साथ गठजोड़ करेंगी।

तीन स्टेप में 'तत्काल'

- एनपीएस तत्काल की भी शुरुआत की गई है। इसमें भीम जैसे यूपीआई ऐप्स और बैंकों के ऐप पर एनपीएस खाता सिर्फ तीन स्टेप में खोला जा सकेगा।
- 1) जन्मतिथि भरनी होगी।
- 2) बैंक खाते का ब्यौरा देना होगा।
- 3) अपना पेंशन फंड में अपना कंट्रीब्यूशन।

इस फंड का मैनेजमेंट वैसे ही होगा, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों का होता है। यानी शेयर बाजार में कम पैसा लगाया जाएगा। पिछले कई बरसों में औसत 9 पर्सेंट से ज्यादा का रिटर्न मिला है।

कई और पहल

■ **एनपीएस सेंट्रल :** ग्राहक का खाता किसी भी CRA (Protean, CAMS, KFINTECH) के पास हो, वो npscentral.in पर अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकता है।

■ **पेंशन सहायक :** पेंशन सहायक (pensionsahayak.pfrda.org.in) मौजूद होगा, जो शिकायतें निपटाने के लिए AI से लैस होगा। सिर्फ मोबाइल नंबर और जन्मतिथि से लॉगिन होगा।

■ **पेंशन सखी :** महिलाओं को ट्रेनिंग देकर पेंशन सखी बनाया जा रहा है।

बढ़ सकता है दायरा

अब BHIM ऐप से NPS खाता खोला जा सकेगा। ग्राहकों को अलग से ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने और PRAN के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। खाता खुलने के बाद UPI से किस्तें भी जमा की जा सकेंगी। इससे का दायरा बढ़ेगा। लोग UPI से रिटायरमेंट के लिए बचत भी शुरू कर सकेंगे। अभी देश में करीब 2.33 करोड़ लोग NPS से जुड़े हुए हैं। आशा है कि इस पहल से इससे जुड़ने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ेगी।

NBT Lens
खबरों के अंदर की बात

सितंबर में GST कलेक्शन

इस बार सर्दियों में होने वाली बारिश कम होने की संभावना

अल नीनो बढ़ाएगा प्रदूषण की चुनौती

Poonam Gaur
@timesofindia.com

Rajesh Mehta

- अल नीनो से कमजोर पड़ सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस
- सर्दियां इस बार सामान्य से अधिक गर्म रहने की भी संभावना
- बारिश न होने से वातावरण में लंबे समय तक जमा रहेंगे प्रदूषक



अल नीनो के दौरान सर्दियों में मौसम शुष्क रहने की संभावना बढ़ती है

■ नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में इस बार सर्दियों के दौरान प्रदूषण की चुनौती बढ़ सकती है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मजबूत अल नीनो की स्थिति सर्दियों को अपेक्षाकृत शुष्क बना सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि सर्दियों में होने वाली बारिश इस बार कम होने की संभावना है। अल नीनो की वजह से उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश लाने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर पड़ सकते हैं। बारिश के दौर कम होने पर वातावरण में जमा प्रदूषक लंबे समय तक बने रह सकते हैं। साथ ही धान की कटाई के बाद पंजाब, हरियाणा में पराली जलाने से आने वाला धुआं भी दिल्ली की हवा को प्रभावित कर सकता है।

बारिश न होने पर प्रदूषण वातावरण में बना रहता है

स्काईमेट के मौसम विशेषज्ञ महेश पलावत के मुताबिक मजबूत अल नीनो के दौरान सर्दियों में मौसम शुष्क रहने की संभावना बढ़ती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर होने पर उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में होने वाली पैर-मौसमी बारिश कम हो सकती है। सामान्य तौर पर ये बारिश प्रदूषण से अस्थायी राहत देती हैं। IMD के रिटायर्ड DG के जे रमेश के मुताबिक मॉनसून की वापसी के बाद उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में हवा की दिशा धीरे-धीरे दक्षिण-पश्चिम से बदलकर उत्तर-पश्चिम होने लगती है। अक्टूबर-नवंबर में धूप की गर्मी कम होने से तापमान और वातावरण ठंडा होने लगता है। इससे उत्तर-पश्चिम भारत में स्थायी दबाव बनता है। ठंडी और शुष्क उत्तर-पश्चिमी हवाएं दिल्ली को और आगे लाती हैं। इसी समय पंजाब, हरियाणा में धान की कटाई भी शुरू होती है।

दिसंबर-जनवरी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस

मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर और जनवरी में औसतन करीब तीन से चार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं। इनसे होने वाली बारिश और हल्की बर्फबारी दिल्ली में प्रदूषण को राहत दिला सकती है। इस कारण अल नीनो की वजह से बारिश का अभाव पहले की आशंका जताई जा रही है।

पराली जलाने के 137 मामले

पराली बढ़ा सकती है राजधानी की मुश्किलें

■ नई दिल्ली : पराली जलाने के मामलों में इस बार शुरुआती दिनों में थोड़ी कमी दिखी है। पंद्रह दिन बीत जाने के बाद अब तक छह राज्यों में पराली जलाने के कुल 137 मामले सामने आए हैं। हालांकि इस बार पंजाब में धान का रकबा सबसे अधिक रहा है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट (IARI) की रिपोर्ट के मुताबिक, 15 सितंबर से एक अक्टूबर तक पराली जलाने के कुल 137 मामले सामने आए हैं। इनमें पंजाब से 63, उत्तर प्रदेश से 37 और मध्य प्रदेश से 31 मामले हैं। हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली में पराली जलाने के मामलों की संख्या 5 से भी कम है।



इस बार सर्दियां गर्म रहेंगी। बारिश कम होगी। ऐसे में हवाएं परेशानी बढ़ा सकती हैं। इस स्थिति में पराली का धुआं भी राजधानी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। -अनुमिता रायचौधरी, सीएसई

15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक के मामले

राज्य	2020	21	22	23	24	25	2026
पंजाब	1190	228	192	337	155	95	63
हरियाणा	93	11	2	96	84	7	3
यूपी	51	46	13	50	6	46	37
एमपी	26	5	1	29	11	9	31

CM ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का किया उद्घाटन

AI, GPS, CCTV से रियल टाइम नज़र

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर अब आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI), सैटेलाइट्स और सेंसर्स के जरिए रियल टाइम नजर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को हस्तसाल पार्क स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, 700 से अधिक निर्माण स्थलों को आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) और सैटेलाइट्स कैमरों के जरिए 24 घंटे और सातों दिन रियल टाइम निगरानी होगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे।



कंट्रोल रूम से 24 घंटे और सातों दिन होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए अब 'डिटेक्ट, एनालाइज, रूट, रेस्पॉन्ड' के मूलमंत्र पर काम होगा। आईसीसीसी के जरिए प्रदूषण हॉटस्पॉट, निर्माण के उल्लंघन और प्रदूषण के स्रोतों की पहचान का सर्वाधिक विभागों को तत्काल सूचना दी जाएगी। आईसीसीसी से 79 एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशनों, स्मार्ट सेंसिंग सिस्टम्स के मूल्यांकन पर काम होगा। आईसीसीसी के जरिए पेरो ले सकेंगे।

'जन सुझाव पोर्टल से बढ़ेगी जन भागीदारी'

प्रदूषण नियंत्रण में जनभागीदारी अहम है। 'जन सुझाव पोर्टल' के जरिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। अच्छे सुझाव देने पर सम्मानित किया जाएगा। हमारा लक्ष्य जनभागीदारी के साथ प्रदूषण नियंत्रित कर डैम स्टेज-4 जैसी स्थिति से बचना है। -मनजिंदर सिंह सिरसा, पर्यावरण मंत्री

कमांड सेंटर में खास

- दिल्ली के 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले निर्माण स्थल पर रैपिड टीमें।
- फील्ड में तैनात गाड़ियों पर GPS
- वायुदूत टीमें कोई कैमरा पहचान चिह्नित कर उतारेंगी।
- सफाई में लगी मशीनें GPS से कमांड कंट्रोल सेंटर से जुड़ेंगी।

■ यमुना की सफाई में अब जनता भी बनेगी भागीदार

यमुना की सफाई को जनभागीदारी से जोड़ने के लिए CM रेखा गुप्ता ने शुरुआत की DU के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से 'मैं भी यमुना प्रहरी' ऐप लॉन्च किया। सीएम ने कहा कि यमुना के स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए शुरुआती जो सहित भागीदारी जरूरी है। सीएम ने कहा कि 18 अक्टूबर को DU के 30 संस्थानों के हजारों विद्यार्थी एक साथ यमुना की स्वच्छता और संरक्षण का संकल्प लेंगे। कार्यक्रम में उपेंद्र सचदेव सिंह व केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा मौजूद रहे।



डीयू के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सीएम ने लॉन्च किया 'मैं भी यमुना प्रहरी' ऐप

सुप्रीम कोर्ट और संसद की सख्ती के बाद कैंसर के महंगे इलाज पर लगाम की तैयारी में केंद्र

कैंसर की जांच से लेकर दवाओं तक के लिए बनाया जाएगा नया राष्ट्रीय रोडमैप

हिमांशु अरविंद मिश्र



नई दिल्ली। देश में कैंसर के महंगे इलाज और जीवनरक्षक दवाओं की भारी कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों और संसद की स्थायी समिति के मंथन के बाद केंद्र सरकार ने इस दिशा में निर्णायक कदम उठाने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार अब कैंसर की प्राथमिक जांच, आधुनिक तकनीक और दवाओं के सटीक इस्तेमाल के लिए एक व्यापक व मानक रोडमैप तैयार कर रही है।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह तय करना है कि किस कैंसर में कौन-सी जांच, थेरेपी और दवा सबसे प्रभावी व जरूरी है, ताकि मरीजों को गैर-जरूरी महंगे जांच से बचाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय प्रस्तावित रोडमैप के तहत कैंसर के हर चरण के लिए मानक उपचार प्रोटोकॉल को नए सिरे से अपडेट कर रहा है। देखा गया है कि सटीक दिशानिर्देश के अभाव में मरीजों को ऐसी महंगी दवाएं या जांच लिख दी जाती हैं, जिनका प्रभाव सीमित होता है। नई व्यवस्था में तथ्य आधारित इलाज को अनिवार्य बनाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की प्रक्रिया पारदर्शी, तर्कसंगत और मरीज की जेब के अनुकूल हो। कुल मिलाकर दवा, तकनीक या मशीनों को तैयार करने में होने वाले खर्च और आम लोगों तक उसके पहुंचने की कीमत की समीक्षा होगी।

■ **हर जिले में विशेष जांच केंद्र :** सरकार की योजना में कैंसर की जांच को गांवों तक ले जाने पर जोर है। इसके तहत जिला स्तर पर प्राथमिक स्क्रीनिंग तकनीकों का विस्तार किया जाएगा, जिससे शुरुआती चरण में ही बीमारी की पहचान कर इलाज के कुल खर्च को कम किया जा सके। इसके लिए हर जिले के सरकारी अस्पताल में कैंसर की जांच के लिए विशेष केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्तन, मुंह और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जांच के लिए एआई आधारित तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। जांच रिपोर्ट तैयार करने में एआई आधारित टेली-पैथोलॉजी और डिजिटल पैथोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने की भी योजना है।

जांच व इलाज की लागत का आकलन...हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट इन इंडिया (एचटीएआईएन) के जरिये अलग-अलग जांच और इलाज की लागत-प्रभाविता का आकलन किया जाएगा। हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी संसद की स्थायी समिति के सामने भी इस पर चर्चा हुई थी। कैंसर की दवाओं का भी इसी आधार पर आकलन होगा। देखा जाएगा कि कौन-सी दवा किस तरह के कैंसर में ज्यादा उपयोगी है।

एम्स

1,500 से अधिक रोबोटिक सर्जरी के अनुभव के आधार पर डॉक्टरों ने बताया तकनीक का फायदा

रोबोटिक तकनीक से ऑपरेशन को बताया बेहतर

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। गॉलब्लैडर (पित्त की थैली) की सर्जरी में अब रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। एम्स दिल्ली के सर्जनों का कहना है कि मुश्किल मामलों में रोबोटिक-असिस्टेड सर्जरी सर्जन को शरीर के अंदर की जटिल बनावट को बेहतर तरीके से देखने और अधिक सटीकता से ऑपरेशन करने में मदद कर सकती है। एम्स के सर्जिकल डिसिप्लिन्स विभाग के डॉक्टरों को अलग-अलग सर्जरी में रोबोटिक तकनीक का 1,500 से अधिक प्रक्रियाओं का अनुभव है। गॉलब्लैडर की सर्जरी सामान्य तौर पर आसान मानी जाती है, लेकिन कई मामलों में ऑपरेशन के दौरान मुश्किलें सामने आ सकती हैं। ज्यादा सूजन, शरीर के अंदर ऊतकों का आपस में चिपक जाना (एडहेसन्स), पुराने संक्रमण या बीमारी के कारण बने निशान और शरीर की सामान्य से अलग बनावट के चलते सर्जन के लिए गॉलब्लैडर के आसपास की संरचनाओं को पहचानना और सुरक्षित तरीके से अलग करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

एम्स के सर्जिकल डिसिप्लिन्स विभाग के प्रोफेसर हेमांगा के भट्टाचार्ज के अनुसार, ऑपरेशन से पहले हर मरीज में सूजन, एडहेसन्स या एनाटॉमी में बदलाव का पता लगाना संभव नहीं होता। ऑपरेशन के दौरान सामने आने वाली स्थिति कई बार अनुमान से अलग होती है। ऐसे मामलों में रोबोटिक-असिस्टेड सर्जरी बेहतर विजुअलाइजेशन और इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल के जरिए सर्जन की मदद कर सकती है।

उन्होंने बताया कि रोबोटिक सर्जरी में सर्जन सीधे मशीन को नियंत्रित करता है। यह सर्जन को शरीर के अंदर की तस्वीर को हाई-डेफिनिशन थ्रीडी में देखने और ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करने की सुविधा देता है, जो कलाई की तरह अलग-अलग दिशा में घूम सकते हैं।

नई पीढ़ी के सर्जनों के लिए भी उपयोगी

एम्स के सर्जिकल डिसिप्लिन्स विभाग में सर्जरी यूनिट-4 के प्रमुख प्रोफेसर असुरी कृष्णा ने कहा कि मिनिमली इनवेसिव सर्जरी सीख रहे डॉक्टरों के लिए रोबोटिक तकनीक प्रशिक्षण में भी मददगार हो सकती है। एम्स के सर्जिकल डिसिप्लिन्स विभाग के प्रमुख डॉ. सुनील चुंबर ने गॉलब्लैडर सर्जरी में हुए बदलावों को करीब से देखा है। उन्होंने ओपन सर्जरी, मिनी-लैपरोटॉमी और पारंपरिक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद रोबोटिक-असिस्टेड सर्जरी का अनुभव लिया है। उनके अनुभव में रोबोटिक-असिस्टेड सर्जरी लैप्रोस्कोपी के बाद अगला अहम कदम है।

www.jagran.com

बदले नियम, गुलाबी गेंद से भी खेल सकेंगे दिन के टेस्ट मैच 16 | बंद चैंबर में टिप्पणी करना आसान, सुरक्षा हटे तो भीगी बिल्ली बनने में देर नहीं लगेगी : दोगी 17

अब जन्म या मृत्यु पंजीकरण कराने में देरी की, तो आसान नहीं होगा प्रमाणपत्र बनवाना



- एक साल बाद और दो साल के भीतर पंजीकरण के लिए शिक्षा या एजीडीएम का आदेश जरूरी
- दो साल बाद पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से जारी करना होगा आदेश

[illegible]

व्यक्तिगत आयकर की गणना सीखेंगे कक्षा नौ के बच्चे

[illegible]

Clean city campaign

Chief Minister Rekha Gupta participates in a cleanliness drive at Kamla Nehru Ridge on Thursday. The mega drive, under the 'Swachhta Hi Seva 2026' campaign, covered around 300 locations in Delhi. Ministers, students, sanitation workers were among the attendees. @GUPTA_REKHA

September AQI in Capital was lowest in 5 years, still PM2.5 and PM10 spiked

Sophiya Mathew
New Delhi, October 1

DELHI'S AIR appeared to improve this September. The city's average Air Quality Index, or AQI – a numerical index that translates concentrations of multiple air pollutants into a single measure of air quality – fell to 102, its lowest September average in five years, according to official data from the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (CAQM).

But measurements of two specific key pollutants — PM2.5 and PM10 — tell a different story.

The concentrations of PM2.5 and PM10, two of the pollutants most closely associated with air pollution, slightly increased this September compared with last year, according to an analysis of data from the Central Pollution Control Board (CPCB).

At first glance, the two sets of numbers appear contradictory. But they measure different aspects of air quality, and the difference largely lies in how the AQI is calculated and how the data is compared.

AQI not an average of pollutants

The National Air Quality Index classifies air quality into six categories: Good (0-50), Satisfactory (51-100), Moderately polluted (101-200), Poor (201-300), Very Poor (301-400) and Severe (401-500).

With an average AQI of 102, Delhi's air in September fell into the 'Moderate' category.

The AQI is a composite measure based on concentrations of individual pollutants, including PM2.5, PM10, nitrogen dioxide, ozone, sulphur dioxide, carbon monoxide, ammonia and others.

For each pollutant, a sub-index is calculated based on its concentration. The overall AQI is determined by the pollutant with the highest sub-index on a given day. This means the AQI is not obtained by simply adding or averaging the concentrations of PM2.5, PM10 and gaseous pollutants.

As a result, a rise in PM2.5 does not necessarily mean the AQI will rise by a corresponding amount. If PM2.5 increases but its sub-index remains below that of another pollutant, the overall AQI can remain unchanged or even fall if the dominant pollutant is at a lower level. The same applies to PM10.

The analysis of the CPCB data for September shows that the average PM10 concentration rose from 104 micrograms per cubic metre (µg/m³) in September 2025 to 106 µg/m³ this year. PM2.5 increased from 35 µg/m³ to 39 µg/m³.

At the same time, the monthly averages of NO2 and ozone were lower than they were in September 2025.

CAQM, meanwhile, reported that Delhi's September average AQI was 102, compared with 105 in both 2025 and 2024, 108 in 2023 and 104 in 2022. So, the decline in the monthly AQI does not mean that concentrations of every pollutant declined. It means the composite AQI outcome was lower.

Why AQI doesn't move with PM2.5 alone

A rise in PM2.5 does not always mean the overall AQI will rise. This is because the AQI is based on several pollutants, and the pollutant with the highest sub-index determines the final AQI.

"If PM2.5 rises from one concentration to another, its sub-index also rises. But if ozone or another pollutant still has the higher sub-index, the overall AQI is controlled by that pollutant. Conversely, if the pollutant that was previously driving the AQI falls substantially, the overall AQI can decline even if PM2.5 or PM10 rises," explained Sunil Dahiya, lead analyst and founder at Delhi-based think tank Envirocatalysts.

He pointed out that month-to-month variations in average AQI can affect the cumulative average when a longer period, such as January to September, is compared with previous years. Even relatively small differences in individual months can result in a slight change in the overall average when aggregated over nine months.

• DELHI AIR QUALITY: JAN 1 TO SEPT 28

AQI below 200

YEAR	DAYS
2022	146
2023	193
2024	188
2025	187
2026	194

Poor to severe+ days

YEAR	DAYS
2022	127
2023	80
2024	86
2025	86
2026	79

AQI above 500 is classified as Severe+

Cumulative PM2.5
Average over the 9 months

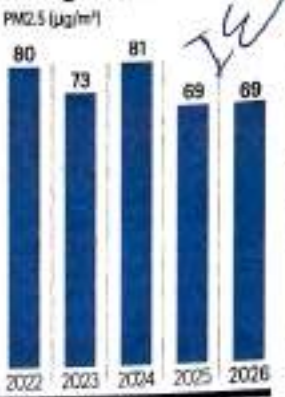

SOURCE: CAQM DATA

• Skywatch

Forecast: October 2, 2026
Mainly clear sky. No rain.
MAX: 33-35
0.3°C above normal
MIN: 21-23
0.3°C below normal

• AQI Tracker



Jahangirpuri
Poor
AQI: 218



Sonia Vihar
Moderate
AQI: 159



Dwarka
Poor
AQI: 205



Aya Nagar
Moderate
AQI: 143

- Good (0-50)
- Satisfactory (51-100)
- Moderate (101-200)
- Poor (201-300)
- Very Poor (301-400)
- Severe (401-500)

Govt launches control centre to monitor pollution sources

New Delhi: Chief Minister Rekha Gupta Thursday launched an Integrated Command and Control Centre of the Delhi Pollution Control Committee for real-time monitoring of various sources of pollution in the city, AI-based analysis of pollution data and tracking of road sweeping machines.

The centre, located at Delhi Metro Rail Corporation IT Park in Shastri Park, will generate real-time information which will be linked to field-level action, the government said. During the winter, 78 sub-division-level teams will be deployed for monitoring and enforcement. Once a pollution hotspot is identified, the department concerned will be alerted. Subsequent movement of field teams will be monitored through GPS-enabled vehicles, said the government.

Environment Minister Manjinder Singh Sirsa said more than 700 construction sites are being monitored with the help of AI and CCTV cameras.

Gupta also launched a 'Jan Suggestion' portal. "Citizens will be able to share suggestions, complaints, pollution-related concerns through the portal," she said. ENS

महिलाओं की कैंसर सर्जरी में खतरे के दो बड़े हिस्सों की पहचान

- सर्जरी को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में एम्स के डाक्टरों की महत्वपूर्ण खोज
- सर्जन को आपरेशन के दौरान रक्तस्राव और महत्वपूर्ण अंगों को चोट से बचाने में मदद मिलेगी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: महिलाओं में कैंसर की जटिल सर्जरी को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने की दिशा में एम्स के डाक्टरों ने महत्वपूर्ण खोज की है। एम्स सर्जिकल आंकोलाजी विभाग के प्रोफेसर डा. एमडी रे और उनकी टीम ने शरीर में दो ऐसे संवेदनशील हिस्सों की पहचान की है, जहां आपरेशन में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इनकी गर्भाशय मुख, गर्भाशय और अंडाशय के कैंसर के लिए की गई 255 रेडिकल या माडिफाइड रेडिकल हिस्टेरेक्टमी सर्जरी के अध्ययन के बाद पहचान की गई। रक्तस्राव और अंगों को चोट पहुंचने के कारणों का विश्लेषण किया गया। इसके बाद 105 मामलों में सर्जरी की तकनीक में बदलाव किया गया। इससे सर्जनों को आपरेशन के दौरान रक्तस्राव और महत्वपूर्ण अंगों को चोट से बचाने में मदद मिलेगी और इलाज करने में भी काफी आसानी होगी।

पेशाब की नली और नसों को बचाने में मदद: डा. एमडी रे के अनुसार पहली पहचान गर्भाशय की प्रमुख रक्त वाहिकाओं के ठीक नीचे श्रोणि (पेल्विस) की गई है। यहां पर गुर्दे से मूत्राशय तक पेशाब पहुंचाने वाली नली (यूरेटर), मूत्राशय, श्रोणि की नसें और महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाएं एक-दूसरे के बेहद करीब होती हैं। यहां जरा सी चोट लगने से अधिक रक्तस्राव, पेशाब संबंधी समस्याएं और फिस्टुला का खतरा रहता है। सर्जरी के दौरान खून की नसों को एक-एक करके बांधने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इससे खून बहने और पेशाब की नली या आसपास के अंगों को चोट लगने का खतरा कम होगा।

लिवर के पास भी खतरनाक हिस्से की पहचान: डा. एमडी रे ने बताया कि दूसरा हिस्सा लिवर के पास होता है, इसे 'रेज हेपेटोकैवल ट्राएंगल' नाम दिया गया है। लिवर को आसपास के टिश्यू से अलग करने या उसे हटाने के दौरान यहां बड़ी रक्त वाहिकाओं को चोट लगने से गंभीर रक्तस्राव हो सकता है। इन दोनों हिस्सों की पहचान का उद्देश्य सर्जनों को आपरेशन के दौरान जोखिम वाले स्थानों के प्रति पहले से सचेत करना है। इससे सर्जरी में सटीकता बढ़ाने, महत्वपूर्ण अंगों और नसों को सुरक्षित रखने तथा मरीजों की रिकवरी और जीवन गुणवत्ता बेहतर करने में मदद मिल सकती है।